

## प्रेस विज्ञप्ति अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय COVID-19 आजीविका सर्वेक्षण: आकड़ों के पीछे की कहानियां

बिहार, झारखण्ड, मध्य प्रदेश एवं ओडिशा

बुधवार , 3 जून 2020

कोरोना-तालाबंदी के चलते, रोजगार और आजीविका पर पड़े असर और इससे राहत पाने के लिए घोषित सरकारी योजनाओं को समझने के लिए, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी ने भारत के 12 राज्यों में 5000 कर्मचारियों का विस्तृत फोन सर्वेक्षण किया है। इस सर्वेक्षण को कराने में दस सिविल सोसाइटी संघटनों ने यूनिवर्सिटी का सहयोग किया है। सर्वेक्षण से जुड़ी सभी जानकारी जैसे कि आंकड़े एवं सहयोगी संगठनों का विवरण हमारी वेबसाइट पर [वेबसाइट](#) पर उपलब्ध है। राज्यवार सर्वेक्षण डाटा भी [यहाँ](#) उपलब्ध है।

इस वेबिनर में मुख्य रूप से हम बिहार, झारखण्ड, मध्य प्रदेश और ओडिशा में किये गए सर्वेक्षण के निष्कर्ष पेश करेंगे। हमारे साथ काम कर रही संस्थायो के माध्यम से हम यह समझ बना पाएंगे की उन गाँव एवं शहरों में जहा वह काम कर रहे है वहा इस सर्वेक्षण के परिणामो के क्या मायने है।

आप से अनुरोध है की [यूट्यूब लाइव](#) पर हमसे जुड़ें।

कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम के लिए २४ मार्च से लगी तालाबंदी ने अर्थव्यवस्था पर और विशेष रूप से कमजोर, अनौपचारिक, प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवारों पर गहरा वार किया है। इनका मुकाबला करने और आर्थिक सुधार के मार्ग को तय करने के लिए हमे तत्कालीन उपायों के साथ साथ, मध्यम से लंबी अवधि के लिए, व्यापक नीतिगत उपायों की भी जरूरत पड़ेगी। हम आशा करते हैं कि इस सर्वेक्षण से निकले निष्कर्ष, नीतिगत हस्तक्षेपों की सीमा और प्रकृति को निर्धारित करने में मदद करेंगे। तालाबंदी लागू होने के बाद के रोजगार और कमाई की स्तरों को माप कर हमने इनकी तुलना फरवरी के आंकड़ों से की है। सर्वे में स्व-रोजगार, दिहाड़ी मज़दूर और नियमित वेतन / वेतनभोगी कर्मचारियों की स्थिति का अध्ययन किया गया है।

यह सर्वे सिविल सोसायटी संगठनों और सहयोगियों के नेटवर्क के चुनिंदा सैंपल के जरिए किया गया है. निष्कर्ष केवल सैंपल से संबंधित हैं और ये पूरे राज्य का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। अतः निष्कर्ष को सभी राज्यों के साथ तुलना नहीं की जानी चाहिए।

### सर्वेक्षण के प्रमुख निष्कर्ष

#### बिहार (ग्रामीण, 173 प्रतिवादी )

- लगभग आधे (46%) श्रमिकों ने अपना रोजगार खोया है। | दिहाड़ी मज़दूरों पर ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ा है | 10 में से 8 लोगों ने अपना रोजगार खोया है।
- OBC (35%) कर्मियों की तुलना में SC/ST (58%) कर्मियों ने ज्यादा रोजगार खोया।
- 10 में से 7 घरों में तालाबंदी के दौरान लोगों ने अपने खाने की मात्रा में कमी की।
- करीब 85% SC/ST घरों ने अपने खाने की मात्रा में कमी की।
- आधे से ज्यादा (56%) वंचित परिवारों को जन धन खाते में पैसा नहीं मिला।
- 10 में 4 वंचित परिवारों को कैश ट्रांसफर के माध्यम से पैसा नहीं मिला।

### झारखण्ड (ग्रामीण, 458 प्रतिवादी )

- लगभग 10 में से 6 (58%) श्रमिकों ने अपना रोज़गार खोया है ।
- दिहाड़ी मजदूरों पर सबसे बुरा प्रभाव पड़ा, 76% ने अपने रोज़गार खोया ।
- 89% किसान या तो अपनी खेती की उपज नहीं ले पाए या सही दामों पर बेच नहीं पाए ।
- 10 में से 4 वेतन कर्मियों को या तो कम वेतन मिला है या कोई वेतन नहीं मिला है ।
- ग़ैर खेती स्वरोजगारी एवं दिहाड़ी मजदूर के साप्ताहिक कमाई में 2/3 (65%) कमी आई ।
- लगभग 10 में से 8 परिवारों ने बताया की उनके खाने की मात्रा में कमी आयी है ।
- 10 में 6 वंचित परिवारों के जन धन खाते में पैसे ट्रांसफर नहीं हुए ।
- आधे से ज्यादा (54%) वंचित परिवारों को किसी प्रकार का नकद ट्रांसफर नहीं मिला ।

### ओड़िसा ( 503 प्रतिवादी )

- दो तिहाई श्रमिकों ने अपना रोज़गार खोया है । | शहरी स्वरोजगारियों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, लगभग 96% ने रोज़गार खोया ।
- 10 में से 9 किसान या तो अपनी खेती की उपज ले नहीं पाए या फिर उसे सही दाम पर बेच नहीं पाए ।
- 10 में से 8 परिवारों ने कहा की उन्होंने अपने खाने की मात्रा में कमी की है | सबसे ज्यादा असर शहरी क्षेत्र के परिवारों (92%) में देखने को मिला ।
- 10 में 9 परिवारों को राशन मिला ।
- 10 में से 7 वंचित परिवारों के जन धन खाते में पैसे ट्रांसफर नहीं हुए ।
- एक चौथाई वंचित परिवारों को किसी प्रकार का नकद ट्रांसफर नहीं मिला ।

### मध्य प्रदेश ( ग्रामीण, 525 प्रतिवादी )

- लगभग आधे (48%) श्रमिकों ने अपना रोज़गार खोया है ।
- दिहाड़ी मजदूरों पर सबसे बुरा प्रभाव पड़ा, 65% ने अपने रोज़गार खोया ।
- 10 में से 7 से ज्यादा किसान या तो खेती से उपज ले नहीं पाए या तो उसे सही दाम पर बेच नहीं पाए ।
- एक चौथाई परिवारों के पास इतना भी धन नहीं था की वो एक सप्ताह का भी ज़रूरी सामान ले पाएं, OBC (17%) और सामान्य (19%) की तुलना में SC/ST परिवारों की स्थिति (25%) ज्यादा ख़राब दिखी ।
- 10 में से 7 परिवार पहले से कम खाना खा रहे थे ।
- 45% वंचित परिवारों के जन धन खाते में पैसे ट्रांसफर नहीं हुए ।
- लगभग 10 में से 4 (36%) वंचित परिवारों को किसी प्रकार का नकद ट्रांसफर नहीं मिला ।
- 

संक्षेप में, अर्थव्यवस्था और श्रम बाजारों को भारी नुकसान पहुंचा है । सर्वेक्षण के निष्कर्षों के अनुसार, आजीविका अभूतपूर्व स्तर पर तबाह हुई हैं । समाधान धीमा और बहुत कष्टकारी हो सकता है । तत्कालीन राहत योजनाएं ज्यादातर अपर्याप्त रहीं हैं ।

सर्वेक्षण के निष्कर्षों को देखते हुए, अध्ययन कर रही टीम ने, इस संकट से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए, निम्नलिखित उपायों का सुझाव दिया है । इन प्रस्तावों का विवरण आने वाली रिपोर्ट में उपलब्ध होगा ।

- पीडीएस प्रणाली को सार्वभौमिक (यूनिवर्सल) बनाया जाना चाहिए और विस्तारित राशन को कम से कम अगले छह महीनों के लिए बांटना चाहिए ।
- दो महीने के लिए कम से कम ₹ 7000 का नकद हस्तांतरण (ट्रांसफर) दिया जाना चाहिए । अर्थव्यवस्था में मांग को वापस लाने के लिए बड़े हस्तांतरण की आवश्यकता है ।
- शारीरिक दूरी के मानदंडों को ध्यान में रखते हुए, नरेगा कार्यों के सतर्क उद्घाटन की तत्कालीन ज़रूरत है ।
- मध्यम अवधि में, मनरेगा के विस्तार, शहरी रोजगार गारंटी की शुरुआत और सार्वभौमिक बुनियादी सेवाओं में निवेश जैसे सक्रिय कदमों की ज़रूरत है ।